चीनी की मिठास को भी था नरेंद्र मोदी का इंतजार

कारोबारी मंत्र

भूपेश भन्डारी

शेयर बाजार में तेजी की बयार में एक क्षेत्र ने अप्रत्याशित लाभ कमाया है। जब से नरेंद्र मोदी की अगुआई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, तभी से चीनी कंपनियों के शेयरों में 15 से 20 फीसदी तक की उछाल दर्ज की जा रही है।

लंबे इंतजार के बाद चीनी उद्योग के दिग्गजों ने कुछ रकम कमा ही ली। इनमें से ज्यादातर की चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में हैं। मिलों पर किसानों का करीब 9,000 करोड़ रुपये बकाया होने के कारण इन कंपनियों के शेयरों पर काफी दबाव था और वे अपने निम्नतम स्तर पर कारोबार कर रहे थे। ये मिलें जिस कीमत पर किसानों से गन्ना खरीदती हैं उसे तय करने का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। चुनावी फायदों के लिए राज्य की सभी सरकारें एक के बाद एक कर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाती रहीं। अधिक कीमत मिलने की वजह से किसानों के लिए गन्ना सबसे आकर्षक फसल बन गई। ज्यादातर किसानों ने गन्ने का रकबा बढ़ा दिया। नतीजतन चीनी की कीमतों में गिरावट का दौर शुरू हो गया। अधिक आपूर्ति और चीनी के गिरते दाम के कारण ही चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का रिकॉर्ड बकाया हो गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने कहा था कि चीनी उद्योग को इस वित्तीय संकट से बचाने का एक ही तरीका है कि गन्ने की कीमतों को चीनी की कीमतों से जोड़ दिया जाए। पिछले साल चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक ने इस फॉर्मूले को अपनाने की पहल की लेकिन उत्तर प्रदेश ने अभी इस नई व्यवस्था की ओर कोई कदम नहीं उठाया है।

गन्ना किसानों के बकाये का बोझ इतना बढ़ गया कि चीनी मिलों का भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रदर्शन से चीनी उद्योग के भविष्य पर काफी चर्चा हो रही है। सपा को उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से महज 5 सीटों पर ही जीत से संतोष करना पड़ा है। कुछ लोगों का मानना है कि इन चुनावों में मिली करारी शिकस्त से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अब यह समझ जाना चाहिए कि गन्ने की राजनीति (राज्य के 80 संसदीय क्षेत्रों में से महज 38 में ही गन्ने की खेती होती है) से वोट नहीं मिलते, इसलिए उन्हें भी राज्य में रंगराजन फॉर्मूला लागू कर देना चाहिए। जबकि कुछ का मानना है कि चुनावों में बुरी हार के कारण वह अक्टूबर से मिलों में शुरू होने वाली गन्ना पेराई के लिए गन्ने की कीमत में और इजाफा कर सकते हैं। हाल में अखिलेश यादव ने कहा था कि पार्टी के समाजवादी मूल्यों को ध्यान में रखते हुए वह कंपनियों के लिए मुनाफे की सीमा तय करने पर विचार कर रहे हैं।

जब गेंद स्पष्ट रूप से अखिलेश यादव के पाले में है तो फिर केंद्र में नई सरकार के आने से चीनी मिलों के शेयरों में क्यों तेजी आ रही है? कुछ समय पहले कुछ चीनी उद्योगपतियों ने मोदी से मुलाकात कर स्थिति की समीक्षा करने को कहा था। इस बैठक में उपस्थित रहे एक उद्योगपति के अनुसार मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वह इस समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। जाहिर तौर पर उद्योग में इस बात को लेकर उत्साह है कि केंद्र की नई सरकार कारोबारियों के प्रति दोस्ताना रवैया रखेगी। इसके अतिरिक्त नरेंद्र मोदी की अगुआई में सरकार कुछ अन्य कदम उठाकर भी चीनी उद्योग की मदद कर सकती है।

एक तो केंद्र ने चीनी उद्योग के लिए ऋण योजना पेश की थी, जिसके तहत बैंकों को ताकीद की गई थी कि वे गन्ना किसानों का बकाया चुकाने के लिए चीनी मिलों को कम ब्याज दर पर 6,600 करोड़ रुपये मुहैया कराएं। इस रकम में से अभी तक मिलों को महज 3,000 करोड़ रुपये ही उपलब्ध कराए गए हैं। बैंक उद्योग को और ऋण देने से परहेज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके ये ऋण पहले से ही उनके बहीखाते पर दबाव डाल रहे गैर-निष्पादित आस्तियों के बोझ को और नहीं बढ़ा दें।

दूसरा केंद्र निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। बल्कि केंद्र सरकार ने निर्यात पर 3,300 रुपये प्रति टन सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य चीनी के निर्यात को बढ़ावा देना था, जिससे चीनी मिलों के पास मौजूद चीनी भंडार को कम कर देसी बाजार में इसकी कीमतों पर पड़ रहा दबाव कम किया जा सके। चीनी निर्यात पर यह सब्सिडी सितंबर 2015 तक जारी रहेगी।

हालांकि इस सुविधा के तहत अधिकतम 40 लाख टन चीनी का ही निर्यात किया जा सकता है, लेकिन अभी तक महज 4 लाख टन चीनी का ही निर्यात किया गया है। चीनी मिलों के मालिकों का कहना है कि हाल में डॉलर के मुकाबले आई रुपये की मजबूती को देखते हुए यह रियायत नाकाफी है। हालांकि मुद्रा विनिमय दर में आने वाले उतार-चढ़ाव को देखते हुए सरकार ने हर दो महीने में सब्सिडी की समीक्षा करने का फैसला किया है। चीनी मिलों ने गुजारिश की थी कि सरकार अगर इसमें बढ़ावा नहीं करे तो इसे इसी स्तर पर बरकरार रखे, लेकिन इस महीने की शुरुआत में ही सरकार ने इस सब्सिडी को घटाकर 2,277 रुपये प्रति टन कर दिया है।

तीसरा, उद्योग नई सरकार से चीनी पर आयात शुल्क 15 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने की गुजारिश कर सकता है। मिलें सरकार से कह सकती हैं कि उनके पास करीब 30 लाख टन चीनी का अतिरिक्त भंडार है और बाजार में आयातित चीनी के लिए लेशमात्र भी जगह नहीं है।

वैश्विक बाजार में कीमत पर दबाव, डॉलर के मुकाबले रुपये में आती मजबूती, सस्ता आयात इस उद्योग के लिए गंभीर जोखिम बने हुए हैं। और आखिर में उद्योग ईंधन में एथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ाने की गुजारिश कर सकता है। फिलहाल चीनी मिलों का कहना है कि उनके पास अगले पांच महीने में शुरू होने वाली पेराई के लिए पैसे नहीं हैं। किसानों ने भी गन्ने का रकबा घटा दिया है। ऐसे में अब सभी की नजरें मोदी पर होंगी कि वह इस संकट का समाधान कैसे निकालते हैं।